# अमेरिका की टैरिफ नीति उलटी पड़ेगी

**भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ अमेरिकी हितों के खिलाफ**

**डेयरी उत्पादन में भारत ने अमेरिका-ईयू को पछाड़ा**

**नई दिल्ली, 08 अगस्त भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च विंग ने एक रिपोर्ट में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि भारतीय सामानों पर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ अमेरिकी हितों के खिलाफ जाएगा और इसका सीधा नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं को होगा. रिपोर्ट में इस कदम को एक खराब नीति निर्णय बताया गया है.**

रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ भारत के साथ व्यापार पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने से अमेरिका और उसके नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि भारत को अपने किसानों को उन वैश्विक कंपनियों की शिकारी प्रथाओं से बचाना जारी रखना चाहिए, जिनकी नजर भारतीय कृषि बाजार पर है.

**कृषि और फार्मा क्षेत्र में भारत की रणनीतिक बढ़त**-श्र रिपोर्ट ने डेयरी क्षेत्र में भारत की प्रगति का हवाला देते हुए बताया कि 2015 से 2024 के बीच भारत ने दूध उत्पादन में यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है. इस अवधि में भारत का दूध उत्पादन 155.5 मिलियन टन से बढ़कर 211.7 मिलियन टन हो गया, जो 36 प्रतिशत की वृद्धि है.

फार्मा क्षेत्र में, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से कैंसर, पुरानी बीमारियों और संक्रामक रोगों के इलाज के लिए सस्ती और उच्च-गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए. एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अमेरिका की लगभग 35 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की जरूरतों को पूरा करता है. यदि इसमें कोई बदलाव होता है, तो कहीं और क्षमता स्थापित करने में कम से कम 3-5 साल लगेंगे.

### अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ

अमेरिका में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च सालाना लगभग 15,000 है. रिपोर्ट चेतावनी देती है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत काफी बढ़ जाएगी. यह भी बताया गया है कि अमेरिकी सरकार के मेडिकेयर और मेडिकेड कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्च का 36 प्रतिशत हिस्सा हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाना सरकार के खर्च को कम करने के उद्देश्य के विपरीत है और इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और निजी जेब से होने वाला खर्च दोनों बढ़ेगा.

# 2030 तक पूरी तरह हरित होगी जियो

**नेट ज़ीरो लक्ष्य के लिए बहु-स्तरीय योजना**

**23,699 साइट्स पर सौर पैनल लगाए गए**

**मुंबई, 08 अगस्त (वार्ता) रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसकी दूरसंचार सेवा इकाई रिलायंस जियो वर्ष 2030 तक पूरी तरह से हरित ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर देगी.**

हाल में जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने साल 2035 तक नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा है, और इसके लिए वह कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है. रिलायंस जियो वर्ष 2030 तक 100 फीसदी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेगी. अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी ने 23,699 स्थानों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए हैं जिनसे 212 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. इसके अतिरिक्त, जियो ने कर्नाटक के बीदर में 35 मेगावाट क्षमता वाला एक केंद्रीकृत सौर संयंत्र भी स्थापित किया है. जियो अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ऊर्जा दक्षता में आगे है. जीएसएमएआई ने एनर्जी बेंचमार्किंग पर अपनी मार्च 2025 की रिपोर्ट में माना कि जियो की प्रति जीबी ट्रैफिक पर ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का लगभग 30 प्रतिशत है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया है कि उसने गुजरात के कच्छ में सौर ऊर्जा प्लांट के लिए भूमि का विकास शुरू कर दिया है. कंपनी की यहां 150 अरब यूनिट बिजली निर्माण की योजना है. कंपनी जल्द ही गुजरात के कांडला में दो हजार एकड़ में ग्रीन कैमिकल के उत्पादन का काम भी शुरू करने जा रही है. कांडला और लकड़िया-1 में दो एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भी रिलायंस को मिले हैं.

# जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री बढ़ी

**नयी दिल्ली, 08 अगस्त (वार्ता) इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री जुलाई में 4.83 प्रतिशत बढ़कर 1,88,891 इकाई पर पहुँच गयी. पिछले साल जुलाई में देश में 1,80,185 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे.**

ऑटोमोबाइल डीलर संगठनों के महासंघ (फाडा) द्वारा शुक्रवार को जारी आँकड़ों में बताया गया है कि जुलाई में दुपहिया वाहनों की बिक्री 4.35 प्रतिशत घटकर 1,02,973 इकाई रह गयी. जुलाई 2024 में देश में कुल 1,07,655 दुपहिया वाहन बिके थे.

फाडा के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने जुलाई की बिक्री के आँकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि जुलाई 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में तेजी जारी रही. दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सेगमेंट में बिक्री बढ़ी है.

दुपहिया वाहनों में ईवी की बाजार हिस्सेदारी जुलाई में 7.5 प्रतिशत है. वहीं, तिपहिया श्रेणी में ईवी की बाजार हिस्सेदारी 62.1 प्रतिशत पर पहुँच गयी. यात्री वाहनों के मामले में ईवी की बाजार हिस्सेदारी 4.7 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों में 1.63 प्रतिशत रही.

# लाभार्थियों का आवास फायनेंस द्वारा सम्मान

**उदयपुर में हुए कार्यक्रम में लाभार्थियों की सफलता का जश्न**

**आवास फायनेंस के एमडी बोले-हर परिवार को घर देना हमारा लक्ष्य**

**उदयपुर, 08 अगस्त अफ़ोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी, आवास फायनेंसियर्स, ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया.**

यह कार्यक्रम उदयपुर में आयोजित किया गया, जहाँ योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले परिवारों की खुशी में सभी शामिल हुए और उन्हें उनके नए घर की उपलब्धि पर बधाई दी गई.

इस समारोह में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण, सिक्किम सरकार के समाज कल्याण विभाग की सचिव सारिका प्रधान, नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी संजय शुक्ला, और बोर्ड सदस्य प्रभंजन मोहापात्रा समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे. इस अवसर पर आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ सचिन्दर भिंडर ने कहा, भारत के हजारों परिवारों को उनके स्वयं के घर का सपना साकार होते देखना हमारे लिए अत्यंत गर्व और संतोष की बात है. हम न केवल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि सस्टेनेबल और पर्यावरण अनुकूल घरों के निर्माण के लिए भी प्रयासरत हैं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन परिवारों की सफलता को उजागर करना था, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर का सपना पूरा किया है.

# रूसी तेल खरीद पर सरकार ने नहीं दिए कोई निर्देश : एचपीसीएल

**नई दिल्ली, 8 अगस्त.** सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी एचपीसीएल के चेयरमैन विकास कौशल ने कहा है कि सरकार ने रूसी तेल की खरीद को रोकने या जारी रखने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम कंपनियां केवल आर्थिक आधार पर इस बारे में फैसला कर रही हैं. यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल आयात जारी रखने की वजह से भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के बाद आया है, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा. कौशल ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में एचपीसीएल द्वारा रिफाइन किए गए कुल कच्चे तेल में रूसी तेल की हिस्सेदारी 13.2 प्रतिशत थी.

# 2024 में 99 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए : मंत्री

**2023 की तुलना में विदेशी पर्यटकों में बढ़ोतरी**

**भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बढ़ाया संपर्क**

**नई दिल्ली, 08 अगस्त केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया कि वर्ष 2024 में 99 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए, जो देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. वहीं, इसी अवधि में 3 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विदेश यात्रा की.**

पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2024 में कुल 99,51,722 विदेशी पर्यटक भारत आए. यह आंकड़ा 2023 के 95,20,928 और 2022 के 64,37,467 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है. आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक विदेशी पर्यटक संयुक्त राज्य अमेरिका (18,04,586) से आए.

इसके बाद बांग्लादेश (17,50,165) और यूनाइटेड किंगडम (10,22,587) का स्थान रहा. सरकार ने यह भी जानकारी दी कि 2024 में 77 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की. सऊदी अरब जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 34,23,711 रही, जबकि 21,43,909 भारतीय नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका गए.

> राज्य मंत्री सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि भारत सरकार आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और भारत की वैश्विक पहचान बढ़ाने में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के योगदान की क्षमता को स्वीकार करती है. उन्होंने उल्लेख किया था कि इन कदमों में प्रमुख विदेशी पर्यटन व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में केंद्र और राज्य सरकारों, पर्यटन बोर्डों और उद्योग हितधारकों की भागीदारी का समर्थन करना; पर्यटन रोड शो का आयोजन; स्थानीय टूर ऑपरेटरों और अन्य उद्योग हितधारकों के साथ जुड़ाव; बी2बी बैठकों और परिचित यात्राओं का आयोजन; और सोशल मीडिया सहित भारत पर्यटन प्रचार अभियान शामिल हैं.

# रेप्को होम को पहली तिमाही में मुनाफा

## ऋण स्वीकृति 24.7 प्रतिशत, वितरण 21.8 प्रतिशत बढ़ा

**चेन्नई, 08 अगस्त.रेप्को होम फाइनेंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) के वित्तीय परिणाम जारी कर दिए हैं. कंपनी ने इस तिमाही में 108 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल इसी अवधि में 105 करोड़ रुपये था. मुनाफे में यह 2.4त्न की मामूली बढ़ोतरी है.**

कंपनी द्वारा इस तिमाही में 907 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए, जबकि वितरित राशि 829 करोड़ रुपये रही. पिछले वर्ष की तुलना में यह क्रमश: 24.7% और 21.8त्न की बढ़ोतरी है. कुल आय 441 करोड़ रुपये रही, जबकि शुद्ध ब्याज आय 191 करोड़ रुपये रही — जो 5.9% और 9.5त्न की सालाना वृद्धि दर्शाते हैं. हालांकि पिछली तिमाही यानी वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही की तुलना में कुछ संकेतक कमजोर रहे.

> 30 जून 2025 तक कंपनी की कुल ऋण पुस्तिका 14,690 करोड़ रुपये रही, जो एक साल पहले की तुलना में 7.2% अधिक है. इसमें 52.3% हिस्सा गैर-वेतनभोगी वर्ग और 47.7त्न वेतनभोगी वर्ग का है. आवास ऋणों का हिस्सा 72.4% और गृह इक्विटी उत्पादों का हिस्सा 27.6% रहा.

# अमेरिकी टैरिफ से भारत की वृद्धि दर पर पड़ सकता है असर : मूडीज

**नई दिल्ली, 8 अगस्त.** रेटिंग एजेंसी मूडीज ने शुक्रवार को कहा कि अगर अमेरिका 27 अगस्त से भारतीय निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत आयात शुल्क लागू करता है, तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर छह प्रतिशत रह जाएगी. यह अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए 6.3 प्रतिशत के मौजूदा पूर्वानुमान से 0.3 प्रतिशत अंक कम है. मूडीज ने कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग और सेवाओं के क्षेत्र की मजबूती अमेरिकी शुल्क के दबाव को कुछ हद तक कम करने में सफल रहेगी.

# महंगी दवा बेचने पर होगी कार्रवाई

## सरकार ने तय की दवाओं की कीमतें

**नई दिल्ली, 8 अगस्त.सरकार ने चार आपातकालीन उपयोग वाली दवाओं के फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमतें निर्धारित कर दी हैं.**

इसके साथ ही, कुछ कंपनियों की एंटीबायोटिक्स और दर्द निवारक दवाओं सहित कुल 37 अन्य दवाओं के फॉर्मूलेशन की खुदरा कीमतें भी तय की गई हैं. यह कदम आम जनता को दवाओं की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. आपातकालीन उपयोग वाली दवाओं में इप्रेट्रोपियम प्रमुख है, जिसका इस्तेमाल क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित मरीजों में घरघराहट, सांस लेने में कठिनाई, खांसी और सीने में जकड़न को कम करने के लिए किया जाता है. इसकी अधिकतम कीमत 2.96 रुपये प्रति मिलीलीटर निर्धारित की गई है.

सोडियम नाइट्रोप्रसाइड, जो एक इंजेक्शन है, इसका उपयोग उच्च रक्तचाप की आपात स्थितियों में रक्तचाप को तेजी से कम करने, सर्जरी के दौरान रक्तस्राव को नियंत्रित करने और तीव्र हृदय गति रुकने की स्थिति में किया जाता है.

## समाचार विशेष

# मोदी ने तय कर लिया अपना उत्तराधिकारी?

## पीएम की रेस से बाहर हुए योगी, सियासी गलियारों में आया भूचाल!

**नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमित शाह को देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने पर बधाई दी और कहा कि यह तो बस शुरुआत है. पीएम मोदी का यह बयान सामने आते ही राजनैतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया है. सियासी पंडित सारी कड़ियां घटनाक्रमों की कड़ियां जोड़ने में लग गए तो बीजेपी के अंदरखाने चर्चा चल पड़ी कि पीएम मोदी ने अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया है.**

दरअसल, साल 2019 में 30 मई को गृह मंत्री का पदभार ग्रहण करने वाले शाह ने मंगलवार को 2,258 दिनों का रिकॉर्ड कार्यकाल

पूरा किया. जिससे भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का 2,256 दिनों का कार्यकाल पीछे छूट गया है. शाह का यह रिकॉर्ड जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की छठी वर्षगांठ के साथ मेल खाता है. यह प्रस्ताव उन्होंने ही पारित किया था. एनडीए की संसदीय बैठक में बोलते हुए अमित शाह को सम्मानित करते हुए पीएम मोदी ने उनकी जमकर प्रशंसा की और उन्हें इसके लिए बधाई दी. सूत्रों की मानें तो इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको बता दूं, यह तो बस शुरुआत है, मोदी ने वाक्य पूरा करने से पहले थोड़ा रुकते हुए कहा. हमें अभी बहुत आगे जाना है.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले महीने इस बात पर ज़ोर दिया था कि एक निश्चित उम्र के बाद नेताओं को नई पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने के लिए गरिमापूर्ण तरीके से पद छोड़ देना चाहिए.

### 'अमित भाई उत्तराधिकारी बनने के योग्य'

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक भाजपा सांसद ने कहा, मोदीजी ने यह संकेत ज़रूर दिया कि अमित भाई को अभी लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि वह अभी सिर्फ 60 वर्ष के हैं. यह पार्टी सांसदों के लिए एक संदेश हो सकता है कि अमित भाई उनके उत्तराधिकारी बनने के योग्य भी है. इसके अलावा पीएम मोदी के इस बयान को लेकर एक अन्य भाजपा सांसद का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह तो बस शुरुआत है और हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है.' यह बयान स्पष्ट रूप से, यह किसी एक नेता के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के लिए एक सामूहिक संदेश था.

# गुरुजी के निधन के बाद राजनीति में बदलाव तय

## समन्वय समिति पुनर्गठन और रास उपचुनाव जल्द

**रांची. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद राज्य की राजनीति में अहम बदलाव तय माने जा रहे हैं. अब राज्य समन्वय समिति का पुनर्गठन और राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए उपचुनाव अनिवार्य हो गया है.**

ज्ञात हो कि 2022 में गठित समन्वय समिति की अध्यक्षता स्वर्गीय शिबू सोरेन कर रहे थे. समिति में राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बंधु तिर्की, झामुमो महासचिव विनोद पांडेय और वरिष्ठ नेता फागू बेसरा जैसे नाम शामिल हैं. लेकिन अब गुरुजी के निधन के बाद समिति प्रमुख विहीन हो गई है, जिससे सरकार के लिए इसका पुनर्गठन आवश्यक हो गया है.

### राज्यसभा सीट के लिए छह माह में उपचुनाव जरूरी

शिबू सोरेन के निधन से झारखंड से राज्यसभा की एक सीट रिक्त हो गई है. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, छह माह के भीतर इस रिक्त स्थान को भरने के लिए उपचुनाव कराना अनिवार्य है. गौरतलब है कि 22 जून 2020 को शिबू सोरेन और भाजपा नेता दीपक प्रकाश राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, जिनका कार्यकाल 21 जून 2026 तक निर्धारित है. लेकिन अब गुरुजी के निधन से एक साल पहले ही यह सीट खाली हो गई है.

# एसआईआर पर बंगाल में जंग की तैयारी

**कोलकाता. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत कर दी है. आयोग ने इसे किश्तों में शुरू किया है और जल्दी ही पूरी तैयारी के साथ आयोग इस काम में उतरेगा. ध्यान रहे बिहार के मुकाबले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस एक्सरसाइज को लेकर ज्यादा आक्रामक हैं और इसके विरोध की तैयारी कर रही हैं. तभी चुनाव आयोग ने हालात का अंदाजा लगाने के लिए पहले 11 जिलों के नाम जारी किए हैं.**

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उत्तरी और दक्षिणी बंगाल के 11 जिलों के नाम और 2002 के विशेष गहन पुनरीक्षण के आधार पर बनी मतदाता सूची अपलोड की गई है. मतदान केंद्र के हिसाब से यह मतदाता सूची अपलोड की गई है.

चुनाव आयोग ने इसके साथ ही कहा है कि जल्दी ही बाकी सभी जिलों की मतदाता सूची जारी की जाएगी. इस तरह आयोग ने संकेत दिया है कि 2002 की मतदाता सूची के आधार पर पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान चलाएगी. इसका मतलब है कि जिन लोगों के नाम 2002 की मतदाता सूची में हैं उन्हें कोई दस्तावेज नहीं जमा कराना होगा. वे सिर्फ मतगणना प्रपत्र भरेंगे और उसके बाद जो लोग मतदाता बने हैं उन्हें चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित किए गए दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज के साथ प्रपत्र भरना होगा. आयोग ने जिन 11 जिलों की सूची जारी की है उनमें कूचबिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, बांकुड़ा, हुगली, हावड़ा, उत्तरी व दक्षिणी दिनाजपुर, माल्दा, मेदिनीपुर और नादिया शामिल है. सो, अब बिहार के बाद बंगाल में भी जंग की तैयारी हो गई.

## विशेष | इंडिया ब्लॉक मिलकर तैयार कर सकता है बड़ी रणनीति

# इंडिया ब्लॉक बैठक में गूंजेगा महाराष्ट्र निकाय चुनाव का मुद्दा!

**मंबई. महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है. खबर है कि अक्टूबर के बाद निकाय चुनाव किए जाने है. इसकी घोषणा होने से पहले ही राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. एक ओर महायुति विपक्ष की पार्टी को खाली करने में लगी हुई है. तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष मराठी अस्मिता के साथ चुनाव में लड़ने की रणनीति तैयार कर रहा है.**

इस बीच उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा भी चर्चाओं का विषय

बना हुआ है. कुछ दिन पहले ही शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस खबर पर मुहर लगाई थी. संजय राउत ने जानकारी दी थी कि, इंडिया ब्लॉक की बैठक के लिए राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को खास न्यौता भेजा. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की खास दिलचस्पी देखी गई थी. इसलिए ऐसी चर्चाएं है कि महायुति को मात देने के लिए इंडिया ब्लॉक मिलकर बड़ी रणनीति तैयार कर सकता है. वहीं दूसरी ओर संजय राउत ने एक खबर से सनसनी फैला दी है. शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और मनसे राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव 'निश्चित रूप से' साथ मिलकर लड़ेंगी.

### एक साथ चुनाव लड़ेंगे ठाकरे बंधु

दिल्ली में जब राज्यसभा सदस्य राउत से शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए एकसाथ आने की संभावना के बारे में पूछा, तो उन्होंने हां में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'अवश्य, दोनों ठाकरे परिवार एकसाथ इस पर चर्चा करेंगे.' मुंबई निकाय चुनाव और अन्य नगर निकायों के चुनाव आगामी महीनों में होने वाले हैं. राउत ने कहा कि चचेरे भाइयों के बीच सुलह के बाद से शिवसेना यूबीटी और मनसे के कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि गठबंधन मुंबई, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली के नगर निकायों में बहुमत हासिल करेगा.